विदेशी पूंजी एवं आर्थिक विकास
Foreign Capital and Economic Growth

आज आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि बाह्य सहायता से ही संभव होता है। अर्द्धविकसित देशों की यह समस्या होती है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं होती है जिससे पूंजी निर्माण दर कम रहता है। अतः विदेशी पूंजी के नियंत्रण द्वारा उनके दोषों को दूर करके उसे आर्थिक विकास में सहायक बनाया जा सकता है।

विदेशी पूंजी दो तरह के होते है —

(a) निजी विदेशी पूंजी — इसके अन्तर्गत विदेशी पूंजीपतियों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विनियोग को शामिल किया जाता है।

(b) सार्वजनिक विदेशी पूंजी — सार्वजनिक विदेशी पूंजी तीन प्रकार के होते है —

(1) द्विपक्षीय मँहगी विदेशी ऋण (Bilateral Hard Loan) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को Pound मुद्रा में कर्ज देना।

(2) द्विपक्षीय सस्ती विदेशी ऋण (Soft Loan) USA द्वारा भारत को ~~OP.6~~ C.P.L. 480 (स्थानीय करेंसी) के अन्तर्गत खाद्यान्न बेचना।

(3) बहुपक्षीय विदेशी सार्वजनिक ऋण (Multilateral Loan) IBRD, IDA, IFC इत्यादि द्वारा उपलब्ध कर्ज।

आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी निम्नलिखित भूमिका अदा करती है।

1. प्रारंभिक जोखिम उठाने के लिए —

विकास की प्रारंभिक अवस्था में जोखिम की संभावनाएं काफी अधिक होती है। अर्द्धविकसित देश में जोखिम उठाने वाले उद्यमियों का अभाव होता है। विकास की

प्रारंभिक अवस्था में जोखिम विदेशी पूंजीपति द्वारा उठाया जाता है जो बाद में देशी पूंजीपतियो द्वारा वसूल किया जाता है जिससे आर्थिक विकास होती है।

2. उद्योगों के निर्माण हेतु

आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। उद्योगों के निर्माण के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि विदेशी सहायता से ही संभव होता है।

3. तकनीकी विकास हेतु

विदेशी पूंजीपति जब कहीं भी पूंजी विनियोग करते है तब वे अपने साथ नये नये तकनीकी लाते है जो कि आर्थिक विकास के सहायक होता है। विदेशी पूंजी से ऊंचे तकनीकी विकास की अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है जैसा कि निम्न के चित्र से स्पष्ट है —

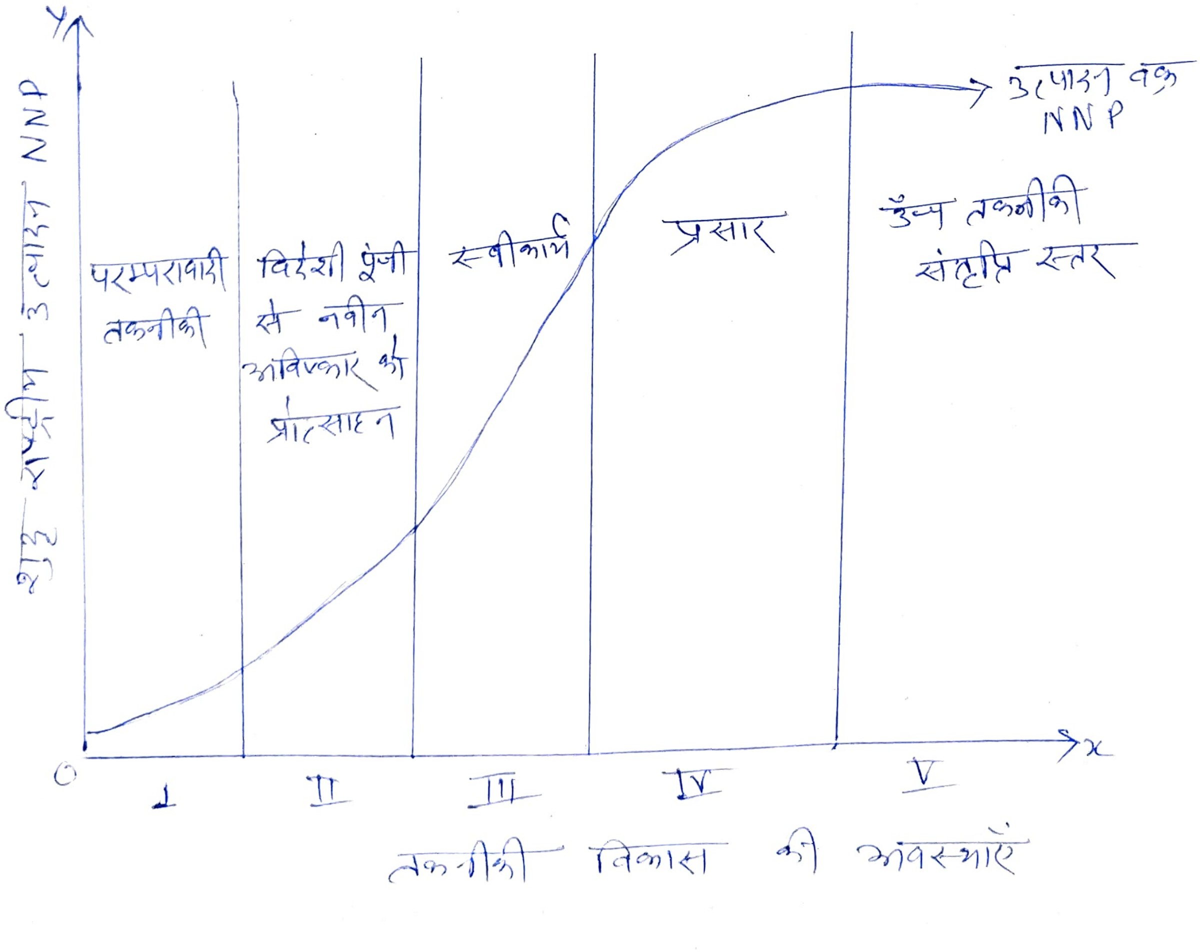

इसप्रकार विदेशी पूंजी के द्वारा नवीन आविष्कार की गति को तीव्र किया जा सकता है जिससे विनियोग बढ़ेगा और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी।

4. परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु

विदेशी पूंजी द्वारा कुछ ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है जिसका बाद में उपयोग देशी लोगों द्वारा होता है। जैसा कि भारत में रेल उद्योग का विकास विदेशी पूंजी से संभव हो सका। उसीतरह राजमार्गों, लोहा तथा इस्पात उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों का विकास विदेशी पूंजी से ही संभव है।

5. औद्योगिक विकास हेतु

औद्योगिक विकास हेतु भी पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि निर्यात से संभव है। चूंकि हमारे देश द्वारा निर्यातित वस्तुओं की मांग बेलोचदार है अतः इसके लिए हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है

6. आयोजन हेतु

आर्थिक विकास के लिए जितना आवश्यक आर्थिक आयोजन है उतना ही आयोजन को पूरा करने हेतु पूंजी। इसलिए देशी पूंजी की अपर्याप्त मात्रा को दूर करने के लिए विदेशी पूंजी को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

7. स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ाने हेतु

विदेशी पूंजी प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है। देशी उद्यमियों को विदेशी उद्यमियों से प्रतियोगिता करने के लिए उन्हें अपनी कुशलता को बढ़ाना पड़ता है।

अतः विदेशी पूंजी आर्थिक विकास के

लिए सहायक होती है। लेकिन विदेशी पूंजी किस मात्रा तथा किस हद तक लिया जाए यह तय कर लेना आवश्यक होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे ~~Trade~~ 'Trade Gap' के द्वारा निर्धारित किया है। जिसे विनिमय अन्तराल भी कहते है। इसे नीचे के चित्र से स्पष्ट किया गया है—

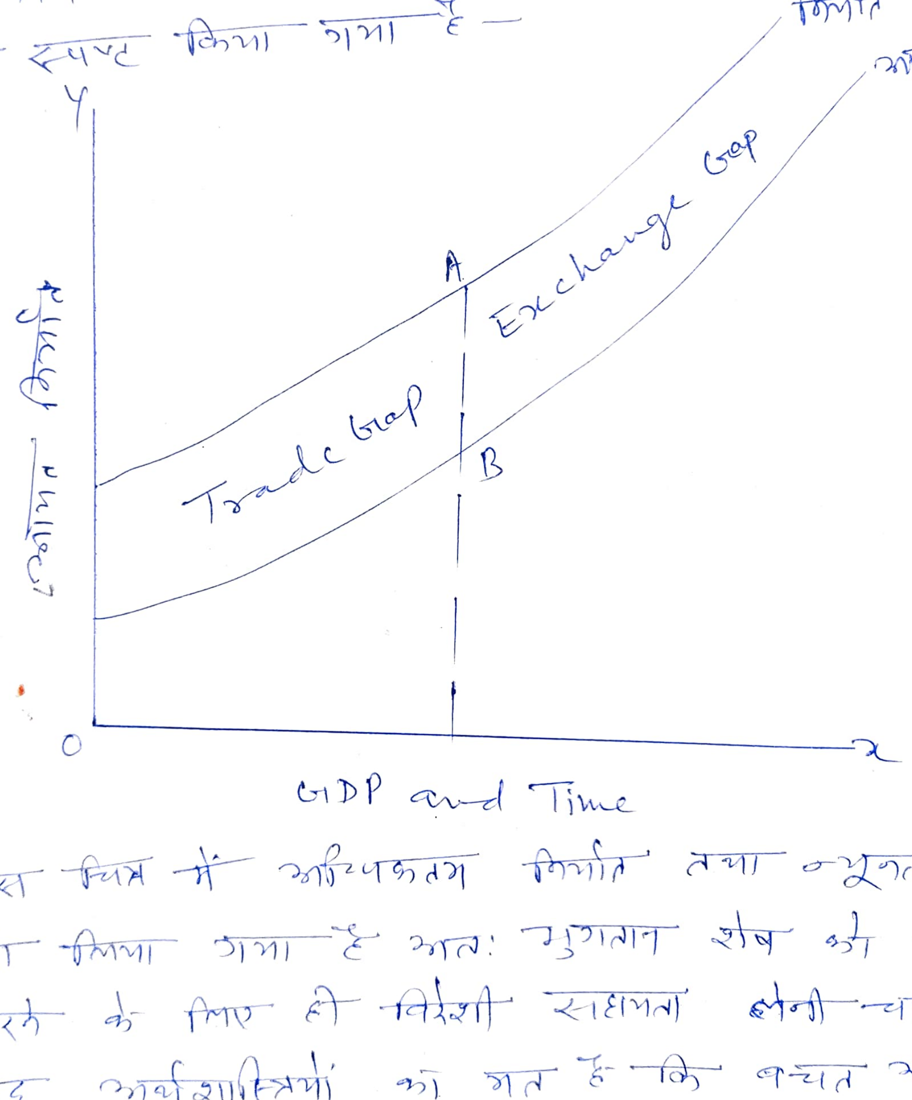

इस चित्र में अधिकतम निर्यात तथा न्यूनतम आयात को लिया गया है अतः भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए ही विदेशी सहायता होनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि बचत अन्तराल Saving Gap को पूरा करने के लिए बाह्य सहायता लेनी चाहिए। इसलिए विदेशी पूंजी की जरूरत अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। विदेशी पूंजी निम्नलिखित शर्तों पर लेना चाहिए—

(1) राजनीतिक प्रतिबंध नहीं हो—

विदेशी पूंजी स्वीकार करते समय यह जरूरी है कि

राजनीतिक प्रतिबन्ध नहीं हो।

2. पूंजी निर्माण में बाधा न होना

ऐसा न हो कि विदेशी पूंजी लेकर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो पूंजी निर्माण में बाधा हो जाएगा।

3. बाह्य वित्त प्रबन्ध के तरीके

बाह्य वित्त कई स्त्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसके निम्नलिखित प्रमुख है—

(a) निर्यात प्रोत्साहन (b) आयात प्रतिस्थापन (c) विदेशी सार्वजनिक ऋण (d) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीयों से विदेशी मुद्रा में ऋण (e) विदेशों से प्राप्त अनुदान

विदेशी पूंजी लेने से पहले बाह्य वित्त के अन्य स्त्रोतों को उपयोग में लाना जरूरी है।

4. विदेशी ऋण जाल

विदेशी ऋण की मात्रा दीर्घकालीन हो तथा उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाए ताकि उसे ब्याज समेत लौटाना आसान हो। विदेशी ऋण जाल में देश फंस नहीं जाए इसका सदा ख्याल रखना होगा।

5. भुगतान शेष की प्रतिकूलता को नियंत्रित रखना

भुगतान संतुलन को अनुकूल नहीं रखने पर देश विदेशी ऋण जाल में फंस जाता है।

6. Economic Sanction का खतरा

विदेशी पूंजी का प्रवाह Economic Sanction के कारण घटा दिया जाता है। अगर देश की विदेशी नीति विदेश की सरकार को पसंद नहीं हो। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर विदेशी पूंजी

की मात्रा तथा भुगतान की अवधि का निर्धारण करना चाहिए।

इस प्रकार एक सीमा तक विदेशी पूंजी के प्रवाह को सुगम एवं तीव्र किया जाना चाहिए ताकि देश में कुल निवेश का स्तर ऊंचा हो और गरीबी या दुश्चक्र को तोड़ा जा सके। दीर्घकाल में निर्यात वृद्धि के उपाय किये जाने चाहिए।

Dr Sandhya Rai
Deptt of English